

UPSC CSE 2018 MAINS PAPER 7 OCTOBER 07, 2018 LAW OPTIONAL PAPER - II QUESTION PAPER

विधि (प्रश्न-पत्र-II)

समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों से कृपया अवधानपूर्वक पढ़ें)

दो खण्डों में कुल आठ प्रश्न दिए गए हैं जो हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषों में दिये हैं।

उम्मीदवार को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए प्रदत्त अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उद्देश्य आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्वैज़ सी.ए.ए.) सुझावों के मूलपृष्ठ पर संकेतित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेगा।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ उल्लिखित है, को पालना जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रवाहों की गणना क्रमनुसार की जाएगी। अतिरिक्त रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उन्हें कदा न गका हो। प्रश्न गहरा उत्तर पूर्णिकर में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णरूपेण खाली न कर दें।

LAW (PAPER-II)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question cum Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question cum Answer Booklet must be clearly struck off

खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। विभिन्न प्रावधानों व न्यायिक निर्णयों की मद्दत में अपने उत्तर को समर्थन दीजिए।

Answer the following in about 150 words each. Support your answer with legal provisions and judicial pronouncements : 10×5=50

- (a) "जब जेडिन जया की मुक्ति 'एक्टस नॉन फैसिट रेमन नस मेन्स सॉ रस' सामान्यतः और एक स्वतंत्र निश्चय के रूप में 'मेन्स रस' का कसब तब निश्चय विशेष रूप में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के निर्वचन में प्राथमिक है।"

अन्युक्त को विवेचनाओं के साथ और व्यवस्था निर्णयों के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

"Whether the maxim 'actus non facit reum nisi mens sit rea' in general and the Common Law doctrine of 'mens rea' as an independent doctrine in particular are relevant in the interpretation of provisions of the Indian Penal Code?" Explain the above in the light of juristic opinions and judicial pronouncements.

- (b) नुकसानी की दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त विधि के विकास का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नुकसानों की दृष्टिकोण से विविधता हेतु प्राप्त किस परीक्षण को स्वीकृत देने हैं और क्यों? अपने उत्तर के लिए कारण प्रस्तुत कीजिए।

Critically examine the development of the law relating to remoteness of damages. Which test do you prefer for deciding the question of remoteness of damages and why? Give reasons for your answer.

- (c) अरुणा शानबाग के मामले में ही यह विश्रुत तब की और अनुकम्पा-मृत्यु के सामाजिक-वैधिक, चिकित्सकीय और वैधानिक पहलुओं का अध्ययन में रखते हुए क्या आप उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के कठिन निर्णय (एक परीक्षित समाधान) कायम माना गया (2018) में एक विचार को निश्चयात्मक मानते हैं? समालोचनात्मक विमर्श कीजिए।

In view of the consistent opinion rendered in Aruna Shanbaug case and also considering the socio-legal, medical and constitutional significance of Euthanasia, do you consider that the view expressed by the Constitutional Bench of Supreme Court in Common Cause (A Regd. Society) vs. Union of India (2018) is conclusive? Comment critically.

- (d) "अन्युक्त विधि का सर्वोच्च कार्य हानियों के संशोधन तथा उनकी संभावित क्षति के निवर्तन में महत्वपूर्ण विनियामक भूमिका निभाना करता है और कल्याणकारी राज्य के अभ्युदय तक अन्युक्त विधि तो संशुद्ध व्यक्ति को लक्ष्य का उपशान्त करने का एकमात्र स्रोत था।"

उद्धृत कथन के आलोक में, उपर्युक्त विधि की प्रकृति और विचार की विवेचना कीजिए और अप्रचलित विधि की महत्त्व में अपने उत्तर की समर्थन कीजिए। साथ ही भारत में स्थिति का विवेचन कीजिए।

"The paramount task of the law of torts is to play an important regulatory role in the adjustment of losses and eventuate allocation of their cost and that until the emergence of the welfare state, the law of torts provided the only source for alleviating the plight of the injured."

In the light of the above statement, discuss the nature and scope of law of torts and substantiate your answer with leading case law. Also discuss the position in India.

- (c) "एक मजदूर की मृत्यु जाति धरने की संज्ञा तक इतने प्रतिभा का अधिका अनुमान और विरोधा करता न आशयित नहीं हो सकता है. अभ्युक्त को विश्वास ही वास्तविक भय के अन्तर्गत होना चाहिए, कि मृत्यु अथवा गम्भीर दुर्घटना हमारे का परिणाम होगा, यदि वह अपनी उल्लंघना नहीं करेगा। अज्ञात की विरोधना की अभिविधना करना लगेव एक नश्य न प्रश्न उत्पन्न है।"

उपरोक्त उक्तिगत को विद्यमान विधिक दायनता और न्यायिक निर्णयों के आलोक में स्पष्ट कीजिए।

"Right of private defence to the extent of causing death of an assailant cannot be based on the surmises and speculation. The accused must be under a genuine fear of death or grievous hurt would otherwise be the consequence of the assault, if he does not defend. To determine the existence of apprehension is always a question of fact."

Explain the above proposition in the light of existing legal provisions and judicial decisions.

2. (a) "अधिनियम 300 (4) का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसकी कार्रवाई की सम्भावना मौलिक निश्चिन्ता के निकट होगी।"

उपरोक्त कथन को स्पष्टकर समझाइए।

"Section 300 (4) of the Indian Penal Code will be applicable in cases where the knowledge of the offender as to the probability of death of a person approximates to practical certainty."

Illustrate the above statement.

20

- (b) "गहरी के कर्ष में यदि नहीं होता" (लेटिन भाषा की मूलिक 'वोलेंटी नॉन एट इजुरिया') की व्याख्या कीजिए, क्या लेटिन का अर्थ है लेटिन एटने की गहरी एक ही बात नहीं है? अपने उत्तर को न्यायिक उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।

Explain the maxim 'volenti non fit injuria'. Is the knowledge of risk not the same thing as consent to suffer the risk? Support your answer with judicial pronouncement.

15

- (c) गैडिन (P) के प्रति गैड डायन करने के समान्य आशय के व्यक्तियों के एक समूह ने मिलकर ज़िन्दा करने का निर्णय किया। समूह के एक से अधिक व्यक्तियों ने, सामान्य अज्ञान के अग्रस्थान में, पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार गैड किया। समूह की एक महिला सदस्या ने समूह के कई व्यक्तियों का ऐप करना सुझाव दिया।

ऐसा परिस्थिति में डायन का हल सच सामान्य अज्ञान का अस्मिन् है। समूह के निम्नलिखित सदस्यों का अपराधिक डायन का विवरण कीजिए :

(i) जो योजना ने मदद दी थी, पर जिन्होंने ऐप से मदद नहीं की थी।

(ii) जिन्होंने ऐप किया था।

(iii) अकेले महिला सदस्य, जिसने ऐप का अग्रण करने में बड़े सुविधा दी थी।

A group of persons decided to act in concert with common intention to commit rape on victim (V). More than one person from the group, in furtherance of common intention, acted in concert in the commission of rape as per pre-arranged plan. One lady member of the group facilitated the commission of such rape by many persons of the group.

The essence of liability in such situation being the existence of common intention. Decide the criminal liability of the following members of the group

- (i) Who were members of the plan but did not participate in the act
 - (ii) Who committed rape
 - (iii) The sole lady member who lend full facilities for the commission of rape
- 15

3. (a) छः व्यक्तियों ने एक बैंक के दारो बंद करके चोर करने का निर्णय लिया। वे बैंक-हकाले के लिए गए, लेकिन पुलिस द्वारा रोके गए। इनमें से सभी भागने लगे। पुलिस द्वारा पोंछा करने पर उनमें से एक लड़का [X] ने श्रीमान Y को, जो उनके रास्ते में बाधा बनने का प्रयास कर रहा था, मार डाला। भारतीय दण्ड संहिता के भागों 391 और 396 के प्रकाश में उनमें से एक के दान की गई हत्या के लिए संबंधित दंडित करें।

Six people decided to carry out dacoity of a bank in a village. They went to the bank to commit it, but were intercepted by police. All of them ran away. While the police was chasing them, one of the dacoits [X] killed Mr. Y, who tried to obstruct his way. Decide liability for the murder committed by one of them in view of Sections 391 and 396 of the Indian Penal Code.

15

- (b) "एक स्वामी अपने सेवक द्वारा मिस्टर के दौरान 'केवल एक गोली कारी के लिए करवको होता है' " इसे सामान्य रूप में और विशेष रूप भारतीय पारंपरिक में स्पष्ट करें।

"A master is liable for all acts of his servant done during the course of employment." Explain it in general and from Indian perspective in particular.

15

- (c) लोक सेवकों द्वारा प्रशासन एक गंभीर समस्या बन चुकी है। व्यापक स्तर पर प्रशासन राष्ट्र निर्माण के कार्य की प्रगति में बाधक होता है और प्रत्येक व्यक्ति को इसका भुगतान करना पड़ता है। लोक सेवकों को दक्षता नहीं बढ़ा सकते, जब लोक सेवक अपने दायित्व की पूर्ण सतर्कता और ईमानदारी से करें। अब ऐसे मामलों में दण्ड में सख्त करारों का कोई भी लक्ष्य स्वीकार करना कठिन होता है (मान प्र. राज्य बनाम शम्भु कुमार उपा. (2006) 8 SCC 693)। टिप्पणी कीजिए।

Corruption by public servants has become gigantic problem. Large scale corruption retards the nation building activities and everyone has to suffer on their count. The efficiency of public servant would improve only when the public servant does his duty truthfully and honestly. Therefore, in such cases, it is difficult to accept any plea of leniency in sentence (State of MP vs. Shambhu Nayal Nagar (2006) 8 SCC 693). Comment

20

4. (a) "भारत में अवैधार्थ सीटबाजी सार्वत्रिक है, क्योंकि वह केवल दण्ड के मायनों में प्रयोज्य है न कि अपराध के। सुनन कर में इस व्यवस्था की व्यवस्था में हम अपनी एक प्रक्रिया है सिवाय इसके कि इनमें एक अपराध पीड़ित को प्रतिकार प्रदाना है।" भारतीय आपराधिक व्यवस्था व्यवस्था में ऐसे अपराधों को माफ़ किए जाने का व्यवहारवादीक निरोधन कीजिए। उन सुधारों को भी सुझाएं, यदि कोई है, जिन्हें आप आवश्यक समझते हैं।

"Plea bargaining in India is the truncated one, as it is applicable to sentence only and not to the charge. Equally it is a court-monitored procedure, except that it provides a clause related to compensation to the victim." Critically analyse the retention of such provision in the Indian Criminal Justice dispensation. Also suggest reforms, if any, you understand are necessary.

15

- (b) "एड्स सी० मेहरा बनाम भारत एव० ये मजदूर -कर्मचारी द्वारा पूर्ण उत्पत्ति का निषेध प्रतिपादित किया जा चुका है।" यह कट्टर लायबिलिटी के नियम पर किन सीमा तक सुधार है? दिखायें कीजिए।

"Rule of absolute liability has been expounded by the apex court in M. C. Mehta's vs. Union of India." How far is it a reform over the rule of strict liability? Comment.

15

- (c) "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 A के अन्तर्गत, एक चिकित्सक के आपराधिक दण्डित्व के निर्धारण के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि चिकित्सक के निरुद्ध की गयी शिवालय ऐसे उत्तमलेखन या उपेक्षा की उच्च डिग्री दर्शाते हों जिससे उनकी मनोदशा जान हो, जिसे ऐसी के प्रति उसकी पूर्ण उत्तरदायित्व के लिए दर्शाया जा सके। ऐसी मामलों में उपेक्षा अकेले ही दण्डनीय है।"

अद्यतन न्यायिक प्रतिपादनों के आलोक में, उपर्युक्त कथन को स्पष्ट कीजिए।

"For fixing criminal liability of a doctor under Section 304-A of the Indian Penal Code, it is necessary to prove that the act complained against the doctor must show such rashness or negligence of such higher degree as to indicate mental state which can be described as totally apathetic towards patient. Such gross negligence alone is punishable."

In the light of the latest judicial pronouncement, explain the above statement. 20

खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। प्रत्येक विधिक प्रश्नों और निर्णित कदों की सहायता से अपने उत्तर का समर्थन कीजिए :

Answer the following in about 150 words each. Support your answer with relevant legal provisions and decided cases :

10×5=50

- (a) यदि निम्न वस्तुओं (सामानों) को या तो शो विन्डो या दुकान के भीतर प्रदर्शित किया जाए और उन वस्तुओं के साथ कीमत चिह्नित भी हो, तो यह विवेचना कीजिए कि क्या यह प्रदर्शन बेचने की प्रस्तावना है। निर्णित कदों की सहायता से प्रस्तावना और प्रस्तावना के आवश्यक वे राज्य गैर स्पष्ट कीजिए।

If certain goods are displayed either in a show window or inside the shop and such goods bear price tags, discuss whether such display amounts to an offer to sell. Explain the distinction between offer and invitation to offer with the help of decided cases.

- (b) अधिवित्त प्रभाव के अधिन एक सविदा के दस्तावेज बनने के कार्य में लड़ों को दो बिन्दुओं को सिद्ध करना होता है। उन बिन्दुओं और विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों, जो अधिवित्त प्रभाव की उपधारणा की ओर ले जाते हैं जिससे स्वतन्त्र सहमति दूषित होती है, को व्याख्या कीजिए।

In an action to avoid a contract on the ground of undue influence, the plaintiff has to prove two points. Explain those points and different kinds of relations leading to presumption of undue influence which vitiates free consent.

- (c) भारतीय संधि अधिनियम, 1872 की धारा 28 विधिक कार्यवाही के अवरोधक करारों को शून्य करती है। क्या इस नियम के कोई अपवाद हैं? गुप्तता प्रावधानों और निष्ठा शर्तों की प्रत्यक्षा से विवेचन कीजिए।

Section 28 of the Indian Contract Act, 1872 makes agreements in restraint of legal proceedings void. Are there any exceptions to this rule? Discuss with the help of relevant provisions and decided cases.

- (d) भारत में लोकहित मुकदमेबाजी (पी० आइ० लि०) इस समय में न केवल जनता प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता था और हो कमजोर है, बल्कि इतिहासिक रूप से के लिए प्रयुक्त की गई है जहाँ प्राचीन के हिस्से को भी आगे बढ़ने के लिए की गई है। भारत में लोकहित मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति, उपयोग और दुरुपयोग के साक्ष्य में नवीन प्रमाणों पर विचार कीजिए।

Public Interest Litigation (PIL) in India, of late, has been used not only to represent the unrepresented and weak but also to advance the interest of others. Comment on the recent trends relating to the application, use and misuse of PIL in India.

- (e) प्रौद्योगिकीय रक्षा उपायों (टी० पी० एम०) के प्रसूतीकरण और मान्यता के बावजूद, अकीव कॉपीराइट नियम अनुपेक्षित और कम कारगर के रूप में देखा है। भारत में अकीव कॉपीराइट के संरक्षण पर कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के 2012 के संशोधनों के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

In spite of introduction and recognition of Technological Protection Measures (TPMs), the digital copyright continues to be unsafe and unsecured. Explain the impact of the 2012 Amendments to the Copyright Act, 1957 on the protection of digital copyright in India.

6. (a) "यह भली प्रकार सुस्थापित है कि यदि और जब पैदाश होना, संविदा स्वतः भंग हो जाती है ...। वह दोनों में से किसी पक्षकार की पराजय या मृत्यु पर निर्भर नहीं करता है। यह संविदा के पालन की संभावना के अस्तित्व पर निर्भर होने के प्रभाव पर निर्भर करता है।" संधि के भंग के प्रभावों को विवेचन कीजिए।

"It is well-settled that if and when there is frustration, the dissolution of the contract occurs automatically It does not depend on the choice or election of either party. It depends on the effect of what has actually happened on the possibility of performing the contract." Discuss the effects of frustration of contract

20

- (b) "यदि कोई व्यक्ति मिथ्या अभियोग करता है कि वह किसी अन्य का एजेंट है, मालिक ऐसे कार्य का अनुसमर्थन कर सकेगा यद्यपि कि वह कार्य बिना उसके अधिकार के किया गया था।"

उपरोक्त कथन के आलोक में, विधायक अनुसमर्थन के आवश्यक तत्वों और उनके प्रभाव को विवेचना कीजिए।

"If a person falsely represents that he is an agent of another, the principal may ratify the act even though the same was done without his authority."

Discuss, in the light of the above statement, the essentials of valid ratification and its effect.

15

- (c) 'संयोगाधीन विकास' परिभाषित है और विकास के मध्य एक संतुलनात्मक संकल्पना के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनों के तहत इस सिद्धान्त की मान्यता और अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए।

'Sustainable development' has been accepted as a balancing concept between ecology and development. Discuss the recognition and application of this principle under the laws relating to environmental protection in India.

15

7. (a) यदि सरकार की तुल्यता एजेंसी का एक अधिकारी तुम सूचना देन के लिए अधिकृत के रूप में एक चेक के आधार पर एक चेक दस्त करता है, तो क्या यह कानून लिखन अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत ऐसे चेक को प्रवर्तनीय कराया जा सकता है? अधिनियम की धाराओं 138 और 139 के अधीन चेककर्ता (आदेशक) के विधितः दायित्वों के क्षेत्र-विस्तार की विवेचना कीजिए।

If an officer with an intelligence agency of the Government receives a cheque for consideration on the basis of an agreement to pass on intelligence inputs, can such cheque be enforceable under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881? Discuss the scope of the legally enforceable liability of the drawer under Sections 138 and 139 of the Act.

20

- (b) "ई-गवर्नेंस प्रणाली के एक ऐसे नए स्वरूप को प्रकट करती है जिसके लिए प्रयोगात्मक तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलने वाली गतिशील विधियों की आवश्यकता होती है।" भारत में इनकी ई-गवर्नेंस को सुनिश्चित करने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की उपलब्धता पर टिप्पणी कीजिए।

"E governance represents a new form of governance which needs dynamic laws, keeping pace with the technological advancement." Comment on the adequacy of the Information Technology Act, 2000 in ensuring effective E-governance in India.

15

- (c) गढ़ा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 सिविल न्यायालय में प्रस्तुत सिविल विवादों के न्यायालय में अदा निपटारे की व्यवस्था देती है, तथापि वैकल्पिक विवाद समाधान (ए० डी० आर०) के माध्यम से ऐसे विवादों का प्रभाव अति कमजोर प्रतीत होता है। ए० डी० आर० पद्धतियों के माध्यम से विवादों के समाधान की असमर्थता के कारणों का विश्लेषण कीजिए।

Even though Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 provides for out of court settlement of civil disputes filed in a civil court, the impact of such settlement through Alternative Dispute Resolution (ADR) appears to be poor. Analyse the reasons for failure to settle the disputes through ADR modes.

15

8. (a) मानक रूप संधि के कमजोर पक्षकार का बचत करने में न्यायालयों ने बड़ी कठिनाई पाई है, और इसलिए सभी संविदाओं में अनिवार्य शोषण की गणना के विरुद्ध ऐसे बाणजोर पक्षकार के हित की संरक्षा के लिए न्यायालयों ने कुछ तरीके निवर्तित किए हैं। मानक रूप संधि के कमजोर पक्षकार को उपलब्ध संरक्षण के तरीकों को स्पष्ट कीजिए।

The courts have found it very difficult to come to the rescue of the weaker party to a standard form contract, and thus evolved certain modes to protect such weaker party against the possibility of exploitation inherent in such contracts. Explain the modes of protection available to weaker party in a standard form contract.

20

- (ii) आधुनिक माध्यामों में जर्नलिज्म द्वारा विचारणा, कुछ मामलों में न्यायालय का प्रख्यान होने के अलावा, स्वतन्त्र और निष्पक्ष विचारणा में सकलपना का निन्वय प्रतीत होता है। जर्नलिज्म द्वारा विचार का मोटे तौर पर अप्रसंगिक ढंग के प्रख्यान पर और पत्रपत्रों के रिकॉर्डरों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

Trial by media appears to be an affront to the concept of free and fair trial in criminal cases, apart from being a kind of contempt of court in certain cases. Analyse the impact of trial by media on the administration of criminal justice in general and on the stakeholders in particular.

15

- (iv) "रश्विता महात्मा गांधी ने कहा था कि वास्तविक स्वतन्त्रता का अंग्रेजों कुछ के द्वारा सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि उनका अधिकार ऐसे सत्ता के दुरुपयोग पर प्रश्न निहल लगाने की शक्ति को प्राप्त करना है।"

उपरोक्त कथन के अन्तर्गत में, लोक अधिकारियों के दायित्वों का परखण कीजिए और व्याख्या कीजिए कि क्या विद्युत लक्ष्य मात्र सरकारों के जीवन अन्दरने उनका प्रभावशाली बन से अन्तर्गत किया है।

"Mahatma Gandhi, the Father of Nation, observed that the meaning of real freedom is not to acquire authority by few but to acquire the capacity to question the abuse of such authority."

Examine in the light of the above statement, the obligations of the public authorities and explain whether they have discharged it effectively during the last about seven decades.

15
